07 दिसम्बर 2013

## ''भाड़े के स्टिंग कैमरा''—अरुण जेटली

राज्य सभा में विपक्ष के नेता

इकॉनॉमिक टाइम्स के पृष्ठ 4 पर आज एक रिपोर्ट है जिसका शीर्षक है '' डू किंग्स ऑफ स्टिंग ऑपरेशन्स फेस अ क्रेडिट डेफीसिट?''

इसका सार है कि हाल के वर्षों में अनेक वेबसाइट आ गई हैं! अधिकतर को स्टिंग ऑपरेशन्स में विशेषज्ञता हासिल है। उनके पास अपने अस्तित्व या बचे रहने के लिए वित्तीय मॉडल नहीं है! उन्होंने अब सोसाइटी और गैर लाभकारी संगठनों के रुप में अपना पंजीकरण कराना शुरु कर दिया है ताकि पारदर्शिता से बच सकें जो कंपनी कानून के अंतर्गत पंजीकृत किसी कंपनी के साथ होती है। किसी भी कंपनी को नियमित खाते रखने पड़ते हैं और उन खातों का ब्यौरा और बेलेंस शीट हर वर्ष रजिस्ट्रार ऑफ कपनीज़ के पास जमा कराना पड़ता है। यह किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इससे कंपनी की वित्तीय स्थिति पारदर्शी रहती है। यह सुविधा ऐसी स्थिति में उपलब्ध नहीं रहती अगर संचालक कंपनी नहीं है।

मैंने पहले भी कहा था कि ऐसी बहुत सी वेबसाइटों का इस्तेमाल गैर कांग्रेसी नेताओं को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। इसमें जरा भी संदेह नहीं कि नरेन्द्र मोदी इनके निशाने पर मुख्य रुप से हैं। हाल ही में इस तरह की एक जांच आम आदमी पार्टी को निशाना बनाकर भी की गई! किसी तरह के वित्तीय मॉडल के अभाव में ये वेबसाइटें अपना अस्तित्व बचाने के लिए दान पर निर्भर करती हैं।

अदृश्य और गैर पारदर्शी धनराशि किसी भी संगठन के खिलाफ संदेह पैदा करती है। इस तरह के संगठन दान से चलने वाले हो सकते हैं। सच्चाई तो यह है कि सरकार और कांग्रेस पार्टी को आमतौर से इन वेबसाइटों द्वारा निशाना नहीं बनाया जाता जिससे इनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं। जो मसीहा बनने का स्वांग रचते हैं, लगता है जैसे वह खुद साफ हैं। वे अन्य लोगों को पारदर्शिता और खुलापन का पाठ पढ़ाते हैं और इस हद तक बढ़ जाते हैं कि कुछ तथ्यों को बाहर लाने के लिए स्टिंग का सहारा लेते हैं। उनका अपना अस्तित्व अज्ञात स्रोतों पर निर्भर करता है। अब समय आ गया है कि ये वेबसाइट अपने वित्तीय स्रोतों, अपने उद्देश्यों और चुनिंदा लोगों को निशाना बनाने के उद्देश्यों के बारे में सार्वजनिक तौर पर पूरी जानकारी दें।

वरना ये संदेह बना रहेगा कि ये ''भाड़े के स्टिंग कैमरा'' हैं।